



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 198 राँची ,मंगलवार 17 चैत्र 1937 (श०)
7 अप्रैल, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

संकल्प

21 मार्च, 2015

विषय: राँची शहर की व्यापक परिवहन योजना (Comprehensive Mobility Plan) तैयार करने एवं जन निजी भागीदारी (PPP) आधारित मोनोरेल के निर्माण हेतु परामर्शी कार्य के लिए मेसर्स IDFC के चयन करने तथा राँची में Mass Transport System के तहत मोनोरेल पर सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में ।

संख्या-2/नवि0/विविध (Monorail)-09/2013-1074-- राज्य की राजधानी राँची की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.73 लाख है जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है तथा मास्टर प्लान 2037 की समाप्ति तक अनुमानित जनसंख्या-31.6 लाख होगी। मास्टर प्लान में शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना प्रस्तावित की गई है जिसके अन्तर्गत Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार करते हुए जन-निजी-भागीदारी (PPP) के आधार पर Mass Transport System तैयार किया जाना आवश्यक है ।

2. शहरी परिवहन की योजना तैयार करने से पूर्व किसी भी शहर का **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार करना आवश्यक होता है। भारत सरकार द्वारा शहरी परिवहन योजना की स्वीकृति तभी दी जाती है जब उस शहर का **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार हो। इसलिए यह आवश्यक है कि राँची शहर का **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार किया जाय। साथ ही राँची बढ़ती आबादी तथा अन्य राज्यों की राजधानी तथा प्रमुख शहरों में **Mass Transport System** के तहत **Metro Rail/Mono Rail** का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा **Viability Gap Funding** अथवा अन्य योजनाओं के तहत सहायता राशि प्राप्त होती है।

3. राज्य की राजधानी राँची में आवश्यकताओं को देखते हुए **Light Rail Transit System, Monorail System, Metro Rail System** आदि पर विचारोपरान्त तथा शहर में भूमि की अनुपलब्धता, सड़कों के तीखे मोड़ तथा अपेक्षाकृत कम लागत राशि को ध्यान में रखते हुए मोनोरेल का विकल्प बेहतर पाया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या-1757 दिनांक 25 अक्टूबर, 12 जन निजी भागीदारी के माध्यम से राज्य में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को तैयार करने हेतु **Transaction Manager** के रूप में कार्य करने हेतु **IDFC** एवं **JINFRA** को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) तक के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनयन के आधार पर चयनित किया गया है।

5. योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या-1757 दिनांक 25 अक्टूबर, 12 की कंडिका-14 में प्रावधानित एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड, की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई जिसमें मेसर्स **IDFC** के द्वारा राँची शहर की यातायात व्यवस्था के विकल्प के रूप में मोनोरेल के परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके अनुसार यह कार्य निम्नांकित पाँच चरणों में सम्पन्न करने का प्रस्ताव है:-

- **Stage I- Preparation of CMP.**
- **Stage II- Options studies selection of appropriate transit technology.**
- **Stage III- Feasibility assessment and project structuring.**
- **Stage IV- Bid documentation.**
- **Stage V-Bid process management.**

मेसर्स **IDFC** के अनुसार स्टेज-1 के साथ स्टेज 2 एवं 3 की भी तैयारी एक साथ किया जा सकता है। स्टेज-1 **CMP** की तैयारी में नौ माह का समय लगेगा। इसके पश्चात् **Bid documentation** तथा **Bid process management** की कार्रवाई मेसर्स **IDFC** के द्वारा की जाएगी।

दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में राँची शहर में **PPP** मोड पर मोनोरेल चलाने हेतु मेसर्स **IDFC** को आवंटित कार्य करने पर सशर्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है।

6. मोनोरेल के निर्माण में प्रति किलोमीटर व्यय 180 करोड़ रुपये सम्भावित है। प्रथम चरण में कुल 10 किलोमीटर परियोजना लिये जाने का प्रस्ताव है जिसकी संभावित लागत 1800 करोड़ रुपये आयेगी। योजना एवं विकास विभाग के संकल्प के अनुसार व्यवसायिक शुल्क 0.375 प्रतिशत देय होगी जो लगभग 6.75 करोड़ रुपये होगी, जिसका 10 प्रतिशत CMP बनाने पर व्यय होगा। अर्थात् राँची शहर के लिए CMP बनाने में कुल संभावित व्यय 67.50 लाख रुपये होगी ।
7. IDFC द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है कि IDFC फाउंडेशन एक Non-profit making organization है तथा IDFC के Joint Venture Company DIMTS, शहरी परिवहन व्यवस्था की विशेषज्ञ कंपनी है। अतएव यह कार्य DIMTS द्वारा किया जाएगा। सभी Invoice DIMTS द्वारा समर्पित किया जायेगा तथा विभाग द्वारा उन्हें ही भुगतान किया जायेगा। किन्तु उपरोक्त वर्णित 5 चरणों की परियोजना के क्रियान्वयन की सारी जिम्मेवारी IDFC की होगी। पूरी परियोजना की अवधि डेढ़ वर्ष की होगी, जिसे कार्य प्रगति के आधार पर 6 माह तक विस्तारित किया जा सकेगा ।
8. मेसर्स IDFC द्वारा CMP तैयार करने के क्रम में यातायात के अन्य साधनों को बिना बाधित किये हुए सभी मुख्य स्थलों यथा-रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेन रोड, एयरपोर्ट आदि को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाय, इस पर विचार किया जाएगा ।
9. नगर विकास विभाग एवं IDFC के बीच CMP तैयार करने एवं उक्त पर आधारित मोनोरेल का अधिष्ठापन हेतु Memorandum of Understanding (MOU) किया जाएगा जो दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न राज्यस्तरीय कार्यकारिणी की बैठक ने लिए गये निर्णयों के पश्चात् मेसर्स IDFC के द्वारा समर्पित संशोधित MOU प्रारूप के आधार पर किया जाएगा जिसपर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त की जाएगी ।
10. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मार्च, 2015 में मद संख्या- 13 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।
